

प्रेषक,

एल.एन.पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 04 फरवरी, 2013

विषय:-तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि ₹190499000.00 (रुन्नीस करोड़ चार लाख निन्यानबे हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2-उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-

(i) संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमतः वेतन एवं भत्तों तथा पेंशन के भुगतान आदि पर व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

(ii) कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(iii) संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/वित्त परामर्शदाता जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

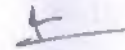
(iv) उपयोगिता प्रमाण-पत्र अध्यक्ष जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड/वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या 19, पूर्वी ब्लॉक सचिवालय देहरादून, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। प्रमाण-पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

(v) वित्तीय वर्ष 2011-12 में अवमुक्त चारों किश्तों व वित्तीय वर्ष 2012-13 में अवमुक्त सभी किश्तों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2013 तक उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अगले

वित्तीय वर्ष की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित समयावधि तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी का होगा।

(vi) संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक -3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थाएं-196-जिला पंचायतें/परिषदें-03-राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करें से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा तथा संलग्नक बी0एम0-15 के कॉलम-4 की बचतों व कॉलम-6 में उपलब्ध कुल धनराशि (अलोटमेंट आई.डी.ए.13.01.0700.60) के अनुसार वहन किया जायेगा।

भवदीय,



(एल.एन.पन्त)

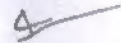
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:- 81 (1)/XXVII(1)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त कुमौऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या 19, पूर्वी ब्लॉक, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,



(एल.एन.पन्त)

अपर सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
(बिहीन बर्ष 2012-2013)

बी.एम.-15

असोसिस्टेड क्लर्क - RI301070060
दिनांक - 29-Jan-2013

अनुदान संख्या - 007
पुनर्वित्तियोग स्वीकृति क्रमांक संख्या -

(In Rupees)

क्रम संख्या	विवरण (1)	आवक नमूना संख्या (2)	बिहीन बर्ष के अनुमानित व्यय (3)	अनुमानित व्यय (4)	सेवाधीनक विवरण द्वारा स्वीकृत व्यय (5)	पुनर्वित्तियोग के लिए अनुमान -6 की तुलना द्वारा (6)	पुनर्वित्तियोग के लिए अनुमान -1 की तुलना द्वारा (7)	अनुमानित
1	20 - सहायक अनुदान/अनुदान/र 904715000	253990000	650723000	2000	20 - सहायक अनुदान/अनुदान/र 904715000	761990000	904713000	
	3604 स्थानीय निकायों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं 02 पंचायती राज संस्थाओं 197 विकास कार्य स्वीकृत पंचायत 03 राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संस्तुत करों से 00 राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संस्तुत करों से (Non Plan Votes)				3604 स्थानीय निकायों द्वारा पंचायती राज 02 पंचायती राज संस्थाओं 196 विकास कार्य स्वीकृत पंचायत 03 राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संस्तुत करों से 00 राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संस्तुत करों से (Non Plan Votes)			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्वित्तियोग से आवक नमूना के परिच्छेद 150,151,155,158 में उल्लिखित प्रावधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।
पुनर्वित्तियोग किये जाने हेतु प्रत्येक 15 की मूल प्रति बिहीन बर्ष 22- सार्वजनिक प्रावधानों, हेतु प्रत्येक की उपलब्ध करा दी जाए

(सहस्रानुमान)
अवर सचिव

शासनादेश संख्या 81 XXVII(1)/2013

दिनांक: 04 जनवरी, 2013 का संलग्न।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में देय चतुर्थ किश्त की धनराशि का विवरण।

₹ हजार में

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	चतुर्थ किश्त हेतु देय धनराशि
1	अल्मोड़ा	13185
2	बागेश्वर	8075
3	चमोली	15886
4	चम्पावत	5831
5	देहरादून	18999
6	हरिद्वार	28998
7	नैनीताल	11363
8	पौड़ी	22758
9	पिथौरागढ़	14471
10	रूद्रप्रयाग	7426
11	टिहरी	13223
12	उधमसिंह नगर	16375
13	उत्तरकाशी	13909
	योग	190499

(रुन्नीस करोड़ चार लाख निन्यानवे हजार मात्र)

(एल.एन.पन्त)

अपर सचिव, वित्त